वर्ष 9 अंक 3 मार्च 1987 दो रुपये

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सीटू वर्किंग कमेटी मिटिंग
कलकत्ता, 6 व 7 फरवरी, 1987

अध्यक्षीय भाषण

बी. टी. रणदिवे

साथियों,

सीटू वर्किंग कमेटी की यह बैठक मुख्य रूप से सीटू के छठे अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए एजेंडा तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए बुलाई गई है, जो 18 से 22 मई तक बम्बई में होने जा रहा है.

सबसे पहले तो मैं, अपनी ओर से तथा आप सब की ओर से भी महाराष्ट्र सीटू तथा उसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष, कामरेड सांभगिरी, को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने अनेक कठिनाइयों के बावजूद, सम्मेलन की मेजबानी की भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है. उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि उन्हें इसका एहसास है कि हमारी शक्ति के जो गढ़ है, उन्हें सम्मेलन की तैयारी के लिए पर्याप्त अवकाश नहीं होगा, क्योंकि मार्च के आखिर तक वे विधान सभा चुनावों में ही व्यस्त होंगे. इसलिए, अगर महाराष्ट्र सीटू ने आगे बढ़कर सम्मेलन की जिम्मेदारी अपनी कंधों पर न ली होती, तो हमें बहुत असुविधा-जनक स्थिति का सामना करना पड़ता.

कामरेडो, सीटू के आगामी अखिल भारतीय सम्मेलन का अपना एक महत्व है और इस सम्मेलन को विचारधारात्मक तथा सांगठनिक रूप से सफल बनाने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए. हमें, मौजूदा हालात के तकाजों की नजर से एजेंडे तथा बहस के लिए तैयारी करनी होगी और बहस के पुराने तरीकों को समाप्त करना होगा.

कामरेडों, सबसे पहले तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए, कि अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को और दूसरे देशों के, खास कर समाजवादी देशों के, ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ बिरादराना सम्बन्धों को, विकसित करें तथा प्रगाढ़ बनायें. हमारे कानपुर सम्मेलन के बाद से, जिसमें सोवियत तथा चीनी ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों ने, युगोस्लाविया की ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने तथा विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के विभिन्न दस्तों से हमारे संपर्कों में प्रगति हुई है. हमें, विश्व संगठनों तथा अनेक समाजवादी देशों की ट्रेड यूनियनों ने और इटली के ट्रेड यूनियन संगठन ने आमंत्रित किया था. हमने, उनके आमंत्रणों को स्वीकार किया और उनके सम्मेलनों में हिस्सा लिया. हमारे प्रतिनिधियों ने, विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सम्मेलन में तथा विश्व शांति सम्मेलन में और इटली की ट्रेड यूनियनों की कांग्रेस में भी हिस्सा लिया. अब इसी महीने हमारे महासचिव समर मुखर्जी, सोवियत संघ की ट्रेड यूनियनों के संगठन, ए यू सी सो टी यू के सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं. जर्मन जनवादी गणराज्य की ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लिए भी हमें आमंत्रित किया गया है. साथियों हम चाहते हैं कि हम भी अंतर्राष्ट्रीय तथा समाजवादी व अन्य देशों के राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों को अपने यहां आमंत्रित करें.

कामरेडों, हमारा सम्मेलन एक ऐसे दौर में होने जा रहा है, जब ट्रेड यूनियन आंदोलन में, हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में, तेजी से घटनाएं घट रही है. हमें बदलते हुए इन हालात का सामना करने के लिए आवश्यक दिशा पकड़ने के लिए सीटू तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन की फौरी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, अपने विचार-विमर्श को नियोजित करना होगा.

हमारे देश में, मजदूर वर्ग की कार्रवाइयों का जबर्दस्त ज्वार उठ रहा है, जिसमें बढ़ती हुई एकता की भावना का बोलबाला है. बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों की शानदार हड़ताल जो अब अपने तीसरे सप्ताह में पहुंच गई है; इससे पहले हुई राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों की जबर्दस्त हड़तालें; सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों कर्मचारियों की 21 जनवरी की विराट तथा शानदार कार्रवाई आदि सभी, तेजी से बढ़ती हुई एकता की भावना और उसके तत्काल जरूरी होने की ओर संकेत करती है. इस मौके पर मैं, सार्वजनिक क्षेत्र की सीटू यूनियनों को तथा उन फेडरेशनों को,

जिनमें सीटू यूनियनें काम कर रही है, इस हड़ताल के आयोजन में पहल करने तथा अनथक काम के लिए वधाई देना चाहूंगा. यह कहना अतिरंजित नहीं होगा कि अगर हमारी यूनियनों ने यह पहलकदमी न दिखाई होती—जिसकी कि सीटू यूनियनों से अपेक्षा की जाती है—तो इस हड़ताल को अपना व्यापक चरित्र हासिल न हुआ होता. मैं बैंक तथा बीमा कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की इस महान तथा जबर्दस्त कार्रवाई में शिरकत की.

इस हड़ताल का महत्व इस बात में है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों-कर्मचारियों की महज कुछ फौरी मांगों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उसकी आत्म निर्भरता तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए की गई हड़ताल थी. इस हड़ताल के जरिए सरकार से यह आग्रह करने का आह्वान किया गया कि वह अपनी आर्थिक नीति बदले, सार्वजनिक क्षेत्र को अस्थिर करने की अपनी नीति बदले.

सालों से ट्रेड यूनियन आंदोलन, मजदूरों की आंशिक मांगों से ही सम्बंधित रहा है और आर्थिक तथा राष्ट्रीय नीतियों के फैसलों को सरकार के भरोसे छोड़े रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र की हड़ताल ने इस बुरी प्रथा को तोड़ा है और देश की आर्थिक नीति को रूप देने तथा उसमें हस्तक्षेप करने के मजदूरों के इरादों को जोरदार ढंग से उभारा है. यही वह दिशा है, जिसकी देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन को जरूरत है—तभी वह एक विशाल जनतांत्रिक तथा समाजवादी शक्ति के रूप में काम कर पायेगा.

सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की अखिल भारतीय विरोध कार्रवाई से और इस कार्रवाई के लिए देशभक्त अफसरान के समर्थन तथा देशभक्त प्रबंधकों की सहानुभूति से सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित होना चाहिए. यह निश्चित है कि जनमत की कद्र करने वाली किसी भी सरकार ने ऐसी विरोध कार्रवाई का आदर किया होता और अपनी नीति पर पुनर्विचार किया होता. लेकिन, राजीव गांधी की सरकार ऐसा क्यों करने लगी जिसे जनता की कोई परवाह ही नहीं है, श्रमिकों के प्रति जिसका रवैया शत्रुतापूर्ण है तथा जो मजदूरों की राय का पूरी तरह तिरस्कार करती है!

बहरहाल, अगर मजदूरों की देशभक्तिपूर्ण मंशा तथा उनकी देशभक्ति की कद्र करने के बजाय अधिकारियों ने मजदूर नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का फैसला लिया, तो इसे मूर्खता की पराकाष्ठा ही कहा जायगा. सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ अधिकारीगण जिन कार्रवाइयों के मंसूबे बना रहे हैं, उनके खिलाफ देश के समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन को सरकार को चेतावनी देनी चाहिए.

सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा तथा उसे मजबूत करने की लड़ाई और जोर-शोर से चलानी होगी. इस लड़ाई के लिए समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन की ताकत को गोलबंद करना होगा, इसमें कोई शक नहीं कि सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों की समन्वय समिति की अगली बैठक में, मजदूरों की एकता को सुदृढ़ करने और हड़ताल के दौरान जो भी कमजोरियां सामने आई है, उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाये जायेंगे.

सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों-कर्मचारियों ने शानदार सफलता के साथ अपना काम पूरा किया है. अगर कुछ संगठन तथा मजदूरों के कुछ हिस्से, जिन्हें इस साझा कार्रवाई में शामिल होना चाहिए था, हड़ताल से अलग न रहे होते और उन्होंने मजदूरों के साथ विश्वासघात न किया होता, तो सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की और भी शानदार जीत होती.

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा की इस विरोध कार्रवाई में शरीक होने से इनकार करके इंटकी नेताओं ने देश, जनता तथा मजदूर वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचाया है. उसके कुछ नेता तो अब सरकार के साथ खुले आम हाथ मिलाकर हड़ताल की निंदा कर रहे हैं. आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन तथा डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन के नेताओं ने भी इस विरोध कार्रवाई में सक्रिय तथा व्यापक भूमिका से इनकार करके अपनी प्रतिष्ठा में कोई इजाफा नहीं किया है, गौरतलब है कि डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन को भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वहां भी निजीकरण हो रहा है तथा मजदूरों को रोजगार ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है और वहां भी मजदूरों ने इसके खिलाफ विरोध की आवाज उठाई थी. अगर इन दोनों संगठनों ने अपने पीछे संगठित मजदूरों को एकजुटता-प्रदर्शनों तथा सभाओं में उतारा होता. तो इससे विरोध की आवाज और मजबूत हुई होती और मजदूर वर्ग की एकता कहीं व्यापक पैमाने पर पुख्ता हुई होती, कुछ नेताओं का यह परंपरावादी, सुधारवादी-अर्थवादी तथा संकीर्णतावादी दृष्टिकोण, ट्रेड यूनियन को भारी क्षति पहुंचा रहा है और देश तथा जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में उसके आड़े आ रहा है.

याद रखना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों-कर्मचारियों ने, सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म किये जाने तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की घुसपैठ के सवाल उठाने के अलावा, ट्रेड यूनियन आंदोलन की पूर्वानुमति के बिना आधुनिकीकरण तथा कंप्यूटरीकरण किए जाने पर रोक की भी मांग की है, यह मांग भी, जो सभी उद्योगों में मजदूरों के रोजगार की हिफाजत करती हैं, सुधारवादी नेताओं को समर्थन देने के लिए प्रेरित करने में विफल रही है.

राज्य सरकार कर्मचारियों की चार-चार हड़तालों और सार्वजनिक क्षेत्र की विराट हड़ताल का तकाजा है कि ट्रेड यूनियन एकता का आधार और ज्यादा व्यापक हो. इस समय राष्ट्रीय अभियान समिति ट्रेड यूनियन एकता का मुख्य औजार है, लेकिन, हाल की ये व्यापक जन कार्रवाइयां ऐसे संगठनों द्वारा संगठित तथा संचालित की गई है, जिनका राष्ट्रीय अभियान समिति के कामकाज में कोई कारगर दखल नहीं है.

राष्ट्रीय अभियान समिति तथा उसकी एकता मुख्यत: पांच या छ: केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की कार्रवाई की एकता पर ही टीकी हुई है. बड़ी-बड़ी फेडरेशनों को, जिनमें से कई तो राष्ट्रीय अभियान समिति के अनेक सदस्यों से भी बड़ी है, राष्ट्रीय अभियान समिति की गतिविधियों में महज आमंत्रितों का ही दर्जा हासिल है. इसलिए, अब यह जरूरी हो गया है कि राष्ट्रीय अभियान समिति के आधार को व्यापक बनाया जाय, ताकि इन बड़ी-बड़ी फेडरेशनों को भी अभियान समिति की बैठकें बुलाने और साझा नीति कार्रवाई के मुद्दों पर फैसला लेने के मामले में समान अधिकार प्राप्त हो सकें.

राष्ट्रीय अभियान समिति ने, ट्रेड यूनियन आंदोलन में एकता तथा साझा समझ के विकास की दिशा में भारी सेवा की है. अब राष्ट्रीय अभियान समिति के गठन को व्यापक बनाकर और फैसला लेने की उसकी प्रक्रिया में, ट्रेड यूनियन आंदोलन की नई विकसित होती हुई शक्तियों की भागीदारी आमंत्रित करके, इस काम को और आगे ले जाने की जरूरत हैं.

ट्रेड यूनियन आंदोलन की मौजूदा स्थिति को, राजनीतिक दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण कुछ मसलों पर मतभेद की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, सीटू ने बहुत पहले ही ट्रेड यूनियन केंद्रों तथा फेडरेशनों के एक महासंघ के गठन का सुझाव रखा था, जिसमें सर्वसम्मति से फैसले लिए जा सकें और श्रम तथा आर्थिक नीति से सम्बन्ध रखने वाले सभी मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जा सके. अब वक्त आ गया है कि हम, अपने सम्मेलन में महासंघ के निर्माण के अपने प्रस्ताव को दुहरायें और उसे जोरदार ढंग से आगे बढ़ायें.

कामरेडों, हमें कानपुर सम्मेलन के बाद के दौर की समीक्षा करनी होगी और अपनी गतिविधियों का आकलन करना होगा. यह आकलन सिर्फ इसी नजर से ही नहीं करना है कि हमने क्या-क्या लड़ाईयां लड़ी हैं, बल्कि इस नजर से भी करना है कि हमने, हमारी राज्य कमेटियों ने तथा ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने अपने आंदोलन को वह दिशा दी है या नहीं, जिसका कि तकाजा था.

यह एक सचाई है कि मजदूर वर्ग के प्रतिरोध के जबर्दस्त उभार के बावजूद, हमारे नेतृत्व में चलाए गए संघर्षों के बावजूद, संकट की मार के चलते मजदूरों की हालत निहायत खस्ता हो जाने के बावजूद और हमारे ट्रेड यूनियन प्रभाव में बढ़ोतरी के बावजूद, हमारे संगठनों की सदस्यता शायद ही कहीं हमारे काम हमारी कुर्बानियों तथा हमारे प्रभाव के अनुरूप होगी. दूसरी ओर, कमजोर इलाकों में ऐसी मिसालें भी सामने आई हैं, जहां सुधारवादी नेता हमें पीछे छोड़कर विशाल जन कार्रवाइयों का नेतृत्व करने में सफल रहे हैं.

इसकी वजह यही है कि हम आज भी ट्रेड यूनियनों के संचालन के परंपरागत तरीकों की दलदल से निकल नहीं पाये हैं. इन कमजोरियों की ओर बार-बार ध्यान खींचा गया है, लेकिन हम अब भी पुरानी आदतों से उबर नहीं पाये हैं.

इन कमजोरियों का सम्बन्ध हैं यूनियनों को जनतांत्रिक ढंग से न चलाये जाने से. यह चीज नीति-निर्माण के फैसलों में आम मजदूरों की सक्रिय तथा उत्साहपूर्ण भागीदारी को रोकती है. इसके चलते यूनियन आम मजदूरों से अनवरत रिश्ता बनाए रखने में विफल हो जाती है और इसका नतीजा यूनियन की सदस्यता के संकुचित बने रहने के रूप में सामने आता है. दूसरी कमजोरियां हैं: अस्थाई मजदूरों, महिला मजदूरों आदि की मांगों तथा हालात को ध्यान में रखने में विफलता. यह चीज, यूनियनों की गतिविधियों को मुख्यत: स्थाई मजदूरों के हितों की रक्षा तक ही सीमित बना देती है.

हमारे कामकाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खामी यह है कि अल्पसंख्यकों तथा उत्पीड़ित जातियों के मजदूरों की विशेष समस्याओं पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है. हम सभी जानते हैं कि इन तबकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिए बिना तथा इन तबकों को साझा संघर्षों में खींचे बिना, फूट-परस्त ताकतों पर कोई वास्तविक आघात करना संभव नहीं है. इसके वावजूद, हमारी रिपोर्टों में ऐसी गतिविधियों का शायद ही कहीं कोई जिक्र होता होगा.

आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी दिनों-दिन बढ़ रही है, स्कूलों या प्रशिक्षण संस्थाओं से निकले या देहाती क्षेत्रों में ऐसे लाखों युवा हैं, जिन्होंने कभी रोजगार का मुंह तक नहीं देखा होगा. फिर भी, सीटू के बार-बार आग्रह करने के वावजूद, ज्यादातर राज्य कमेटियों तथा ट्रेड यूनियनों ने इस समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया है. यह एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि बेरोजगारों की इस नई पीढ़ी का, ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ कोई संपर्क ही नहीं है और शासक वर्ग बड़ी आसानी से उनके गुस्से को संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन के ही खिलाफ मोड़ सकता है.

इस न्यूनतम चेतना का भी अभाव है कि ये बेरोजगार भी मजदूर वर्ग के ही हिस्से हैं और उनके हितों की रक्षा करना संगठित मजदूर वर्ग का कर्तव्य है. इसी उपेक्षा का नतीजा है कि अनेक जगहों में बेरोजगार के इस गुस्से को, अन्य राज्यों से आये मजदूरों से शत्रुता की कट्टरपंथी दिशा में मोड़ा जा सका है. यह एक और फूटपरस्त ताकत है, जो ट्रेड यूनियनों की विफलता के कारण बढ़ती जा रही है.

कामरेडों, हमारा सीटू सम्मेलन तब तक फलदायक नहीं कहा जा सकेगा, जब तक कि ये समस्याएं हमारी बहस के केंद्र में नहीं होंगी. अब, जब, कि हमें अपनी गतिविधियों के बारे में विभिन्न राज्यों की रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी है, हमें अखिल भारतीय सम्मेलन में उन्हें और ज्यादा पुष्पित-पल्लवित करने की कोई जरूरत नहीं है. आगे बढ़ने के लिए, जरूरत इस बात की है कि हम इसका समुचित आकलन करें कि अपनी गति-विधियों के दौरान, नई दिशा देने की ठोस समस्याओं से हम किस प्रकार निपटे है. इसलिए, यह जरूरी है कि सीटू के अखिल भारतीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व

कर रहे वक्तागण इन्हीं प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें और इस सिलसिले में क्या किया गया है , इसका तथ्यात्मक ब्यौरा दें.

मेरी राय है कि कामगार महिलाओं की समस्याओं तथा इस सिलसिले में हमारे काम के प्रश्नों पर विचार को सम्मेलन का एक पूरा सत्र दिया जाय. इसलिए, यह जरूरी है कि हर राज्य इकाई अपने प्रतिनिधिमंडल में कामगार महिलाओं को बड़ी संख्या में भेजे. वास्तव में, हमें सीटू सम्मेलन के साथ ही कामगार महिलाओं का अलग से सम्मेलन आयोजित करना चाहिए था लेकिन, मौजूदा हालात में जब आर्थिक साधनों आदि की तंगी है, कामगार महिलाओं के सम्मेलन के लिए अलग से एक दिन निकाल पाना संभव नहीं हुआ है. इसके अलावा, यह भी जरूरी है कि एक सत्र में बेरोजगारों तथा अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर अलग से विचार किया जाय.

कामरेडो, मैं यहां अपने देश के तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना विकास की चर्चा विस्तार से नहीं करना चाहता हूं, हम, इस सबको ध्यान में रखते हुए, सम्मेलन के लिए अपना प्रस्ताव तैयार करेंगे, हम अपने भाषणों तथा रिपोर्टों में भी उनका जिक्र करेंगे ही. मेरा सुझाव है कि प्रस्ताव कमेटी यहीं गठित कर ली जाय, ताकि वह समय रहते अपनी बैठकें कर सके और सारे प्रस्ताव तैयार कर सके.

फिर भी, हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, उस पर मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूं, यह बहुत ही संतोष की बात है कि कामरेड गोर्वाचोव की भारत यात्रा के परिणामस्वरूप एक संयुक्त घोषणा सामने आई है जिसने शांति के पक्ष को मजबूत किया है और साम्राज्यवादी ताकतों की युद्ध की तैयारियों के खिलाफ आवाज उठाई है. इस संयुक्त घोषणा ने जनता को युद्ध के खतरे के बारे में जागरूक बनाया है और यह बताया है कि इस खतरे के लिए कौन जिम्मेदार है. उसने हमारे देश तथा सरकार द्वारा लागू की जा रही गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के भारी महत्व के बारे में भी लोगों को जागरूक बनाया है. गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को सुदृढ़ बनाने तथा उसकी जड़ें गहरी करने के लिए मजदूर वर्ग को हर संभव कोशिश करनी चाहिए.

कामरेड गोर्वाचोव की भारत यात्रा ने भारत तथा सोवियत संघ के बीच मैत्री को भी गहरा बनाया है. भारत-सोवियत मैत्री तथा सहयोग संधि इसी घनिष्ठ मैत्री का संकेत चिन्ह हैं, जो भारत की सुरक्षा की भी गारंटी करती है. मजदूर वर्ग तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन, इसे एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखता है. यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि जनता के व्यापक हिस्सों को, गुट निरपेक्षता तथा विश्व शांति के लिए संघर्ष में खींचा जाय.

देश की अंदरूनी स्थिति बिगड़ती जा रही है. विदेश नीति के क्षेत्र में, गुटनिरपेक्षता की नीति के क्षेत्र में अच्छे घटना विकास के विपरीत राजीव सरकार की आर्थिक नीतियों ने आत्म निर्भरता के खोखले हो जाने का खतरा पैदा कर दिया है. सार्वजनिक क्षेत्र की हड़ताल के जरिये देश का मजदूर वर्ग पहले ही इन नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा चुका है. इसके साथ ही देश की एकता के खिलाफ फूटपरस्त ताकतों के हमलों और उनके सामने सरकार की असहायता तथा निष्क्रियता से, विद्रोहों तथा अस्थिरता के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.

पंजाब में उग्रवादियों तथा धार्मिक कट्टरपंथियों ने नया हमला बोला है, जिसका मकसद है, बरनाला सरकार को हटाना और धार्मिक आधार पर तमाम सिखों को लामबंद करना. यह हमला ठीक उस समय किया गया है, जब भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थिति नाजुक बनी हुई है और सीमावर्ती इलाकों में लड़ाई के लिए तैयारी की स्थिति में भारी मात्रा में पाकिस्तानी सेनाओं को जमा किया गया है.

इसके अलावा, गोरखालैंड की मांग का फूटपरस्त आंदोलन भी चल रहा है, जिसका मकसद भी जनता को विभाजित करना और फूटपरस्त गतिविधियां चलाना ही है. अगर दो महीने के लिए इस आंदोलन को स्थगित किये जाने का अर्थ वाकई इस मामले में पुनर्विचार करना तथा जनतंत्र के रास्ते पर लौटना हो, तो स्थिति बेहतर साबित हो सकती है. लेकिन, इस आंदोलन को आर्थिक सहायता देनेवाले तथा आंदोलन को वैचारिक दिशा देनेवालों को देखते हुए यह कल्पना कर पाना कठिन है कि समझदारी तथा देश के लिए वफादारी, आंदोलन के नेताओं के बीच फिर से उभरकर सामने आयेगी. आम नेपाली जनता हमारी मेहनतकश जनता का अभिन्न हिस्सा है और हमें हमेशा उसके जनतांत्रिक हितों की रक्षा करनी चाहिए. वाम मोर्चा सरकार ठीक यही कर रही है.

इन चुनौतियों के साथ ही, सांप्रदायिक ताकतों की चुनौती भी सामने आई है. सांप्रदायिक कहलाने वाले लोगों के खिलाफ अपनी सारी लफ्फाजी के बावजूद कांग्रेस पार्टी, केरल में मुस्लिम लीग के साथ अपना गठजोड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. सांप्रदायिक ताकतों के प्रति कांग्रेस की मौकापरस्त नीतियों, दंगों के दौरान प्रशासन की मिलीभगत आदि से मुस्लिम सांप्रदायिकतावादियों के ही हाथ मजबूत हो रहे हैं.

सांप्रदायिक तथा पृथकतावादी खतरे से देश की रक्षा करने का महान काम आज मजदूर वर्ग तथा उसके संगठनों के सिर पर आ गया है. इस सिलसिले में भूमिका अदा करने की अपनी क्षमता अक्सर हम खुद भी, और हमारे विरोधी तो हमेशा ही, कम करके आंकते हैं. वे तो ट्रेड यूनियन आंदोलन को बड़ी भारी बुराई मानते हैं. सार्वजनिक क्षेत्र की हड़ताल, चार राज्यों में राज्य सरकार कर्मचारियों की हड़ताल जैसी हमारी विशाल कार्रवाइयों में सभी जातियों तथा समुदायों के लाखों लोगों का एक साझा मोर्चे में शामिल होना आज के हालात में बहुत माने रखता है, जब कि जनता की साझा वर्ग चेतना का गला घोंटने की हर संभव कोशिश की जा रही है.

ये साझा कार्रवाइयां और जाति तथा धर्म के भेदों से ऊपर उठकर साझा संघर्षों में लाखों छात्रों, युवाओं, महिलाओं आदि की लामबंदी, फूटपरस्त ताकतों की चुनौती को हमारे जबाब हैं. मजदूर वर्ग के हमारे दस्ते असम में, पंजाब में तथा दार्जिलिंग

जिले में यह दिखा भी चुके हैं कि किस प्रकार दृढ़ निश्चय के साथ एक वर्ग, फूटपरस्त ताकतों का मुकाबला कर सकता है. हमारी सभी इकाइयों को इस मिसाल का अनुकरण करना चाहिए, ताकि मजदूर वर्ग राष्ट्रीय एकता की रक्षा के संघर्ष में, अपनी भूमिका अदा कर सके.

कामरेडों, आखिर में मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल तथा केरल में, जनता व मजदूर वर्ग को जल्द ही, शासक पार्टी तथा उसके सहयोगियों के खिलाफ, राजनीतिक लड़ाई में उतरना है, इस लड़ाई में एक ओर आगे बढ़ती हुई जनवादी शक्तियां हैं और दूसरी ओर हैं तानाशाही की ताकतें, जो जनता की प्रगति को उलटना चाहती है.

इस लड़ाई में एक ओर वे शक्तियां है, जो सांप्रदायिकता तथा सांप्रदायिकता पार्टियों के साथ समझौता करती है तथा देश की एकता की रक्षा करने में असमर्थ हैं और दूसरी ओर हैं वे शक्तियां, जो राष्ट्रीय एकता के सवाल पर दृढ़ रुख अपनाती है तथा तमाम सांप्रदायिक व फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ अनथक संघर्ष कर रही हैं. यह सुनिश्चित करने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए कि इन दोनों लड़ाइयों में हमारी जीत हो और देश के समूचे जनतांत्रिक आंदोलन के हक में प्रगति हो. हमारी सभी ट्रेड यूनियनों की जिम्मेदारी है कि चुनावों में वामपंथी ताकतों की मदद करें, ताकि प. बंगाल में वाम मोर्चे की और केरल में वाम जनतांत्रिक मोर्चे की जीत सुनिश्चित की जा सके.

छठे सीटू सम्मेलन को शानदार ढंग से सफल बनाओ

सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने 27-28 जनवरी को अपने दो दिन के बम्बई के दौरे पर, फोर्ट के इलाके में बी यू जे हाल में मध्य वर्गीय कर्मचारियों की और वरली इलाके में जनशक्ति हाल में फैक्ट्री मजदूरों की एक सभा को सम्बोधित किया और सीटू के छठे अखिल भारतीय सम्मेलन को शानदार ढंग से सफल बनाने की अपील की. सीटू का अगला सम्मेलन 18 से 22 मई तक बम्बई में होने जा रहा है.

दोनों ही सभाओं में बोलते हुए, सीटू सचिव ने आजादी के बाद के सारे दौर में कांग्रेस सरकार की नीतियों के चरित्र को बेनकाब किया और बताया कि किस प्रकार मेहनतकश जनता की कीमत पर उद्योगपतियों, जमींदारों, इजारेदारों तथा बहु-राष्ट्रीय निगमों को एक के बाद एक रियायतें दी जाती रही हैं तथा इस तरह की नीतियां जमाखोरों, कालाबाजारियों, थोक व्यापारियों तथा तस्करों को फलने-फूलने का ही मौका दे सकती हैं तथा दे रही हैं.

नृसिंह चक्रवर्ती ने कहा कि "केंद्र तथा राज्यों में इन नीतियों के चलते जनता को असहय तकलीफें उठानी पड़ी है और जब कभी भी जनता ने इसके विरोध में आवाज उठाई है, उसे बर्बर दमन का सामना करना पड़ा है." उन्होंने आगे कहा "यह वाकई दुःख तथा आश्चर्य की बात है कि आजादी के चालीस साल बाद, और ज्यादा रोजगार पैदा होने के बजाय ज्यादा से ज्यादा फैक्टरियां तथा मिलें बंद हो रही है तथा लाखों मजदूरों को बेरोजगार बनाकर सड़कों पर धकेला जा रहा है." सीटू सचिव ने केंद्र सरकार की कंप्यूटराइजेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण तथा आयातों को उदार बनाने की नीतियों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर, मजदूर वर्ग के आम तबकों के बीच तथा ट्रेड यूनियन संगठनों के बीच एकता बढ़ रही है, सार्वजनिक उद्योगों की फरवरी 1983 तथा 21 'जनवरी 1987 की देशव्यापी हड़तालें इसी एकता को प्रतिबिंबित करती है.

सीटू सचिव ने आगे कहा कि उद्योग सम्बद्धी कानूनों के प्रस्तावित संशोधनों से पता चलता है कि आनेवाले दिनों में मजदूर वर्ग को और भी तीखे हमलों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने मजदूरों तथा अन्य मेहनतकशों का आह्वान किया कि वे अपनी व्यापकतम एकता के हथियार के जरिये इन हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें.

अपने भाषण में नृसिंह चक्रवर्ती ने खालिस्तान, गोरखालैंड, झारखंड, 'टी एन वी, हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई आदि विभिन्न संप्रदायों के तत्ववाद आदि, विभिन्न फूटपरस्त ताकतों के खतरे की ओर भी ध्यान खींचा. इस सिलसिले में उन्होंने अमरीकी साम्राज्यवाद और एक ओर सी आई ए जैसे उसके हथियारों और दूसरी ओर विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि की भारतविरोधी भूमिका को रेखांकित किया और बताया कि किस प्रकार अपने इन हथियारों के जरिये साम्राज्यवाद तरह-तरह से हमारे देश की प्रगति तथा स्वतंत्रता का गला घोटने की कोशिश कर रहा है. इस संदर्भ में उन्होंने, शांति के पक्ष में तथा अमरीकी साम्राज्यवाद की युद्ध की तैयारियों के खिलाफ, मजदूर वर्ग की संगठित कार्रवाइयों के महत्व को भी रेखांकित किया.

सीटू सचिव ने अंत में कहा; "यही वह परिस्थिति है, जिसमें सीटू का छठा अखिल भारतीय सम्मेलन बम्बई, में होने जा रहा है. देश के समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए, इस सम्मेलन का भारी महत्व होगा." उन्होंने, बम्बई के मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि इस सम्मेलन को शानदार ढंग से कामयाब बनाय.

प्रभाकर सांझगिरी, के एल बजाज, पी आइ कृष्णन आदि राज्य सीटू नेताओं ने भी इन सभाओं को सम्बोधित किया, दोनों सभाओं में विभिन्न कारखानों के मजदूरों ने फूलमालाएं पहनाकर सीटू सचिव का स्वागत किया. इन सभाओं से पहले नृसिंह चक्रवर्ती ने सीटू की महाराष्ट्र राज्य वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें आगामी सीटू सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की गई.

सीटू के छठे अखिल भारतीय सम्मेलन की ओर

सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक 6 व 7 फरवरी को कलकत्ता में हुई. यह बैठक मुख्य रूप से सीटू के छठे अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए एजेंडा तथा कार्यक्रम तैयार करने तथा विभिन्न राज्य कमेटियां खासकर मेजबान महाराष्ट्र राज्य कमेटी तथा सम्बद्ध यूनियनों के लिए 18 से 22 मई तक से होने जा रही सीटू सम्मेलन के लिए, विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपने के लिए बुलाई गई थी.

वर्किंग कमेटी बैठक के अपने अध्यक्षीय भाषण में, सीटू अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने संक्षेप में आगामी सीटू सम्मेलन के लिए राजनीतिक-विचारधारात्मक परिप्रेक्ष्य रखा. साम्राज्य-वादी युद्ध साजिशें, फूटपरस्त ताकतों की तेज होती गतिविधि, सरकार की नई आर्थिक नीति से उत्पन्न खतरे तथा बेरोजगारी, ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर हमले आदि चुनौतियों की पृष्ठ भूमि में हो रही इस सम्मेलन में परिस्थिति की मांग के अनुसार संघर्षों की समीक्षा पेश करने के लिए उन्होंने राज्य-कमेटियों का आह्वान किया ताकि छठे सम्मेलन में वास्तव स्थिति के आधार पर सही रूप से आगामी संघर्षों के लिए निर्देश दिया जा सके. बी टी आर ने एकजुट संघर्षों को शक्ति-शाली रूप से विकसित करने पर बल दिया. राष्ट्रीय स्थिति से निपटने के अलावा डेलीगेटों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को पूरी तरह समझना होगा और अपने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाना होगा क्योंकि सीटू सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वासी है और सफलता से अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को विकसित किया है.

इसके बाद, बैठक में, आगामी छठे सम्मेलन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई. पी. संभगिरी ने, सम्मेलन स्थल, प्रति-निधियों के ठहरने एवं अन्य इंतजामों के बारे में तथा सम्मेलन के लिए खर्च एवं अन्य तैयारियों के बारे में बताया. बढ़ते कीमतों को मद्देनजर रखते हुए बैठक में सर्वसम्मति से डेलीगेट फी 200 रु निर्धारित किया गया.

का. नृसिंह चक्रवर्ती ने बताया कि अबतक प्राप्त शुल्क के आधार पर सीटू की कुल सदस्यता करीब 17 लाख बैठती हैं. इसीके आधार पर उन्होंने राज्यों के लिए प्रतिनिधियों की संख्या की घोषणा की, जो इस प्रकार है:

अंडमान—1, आंध्र प्रदेश — 110, असम — 40, बिहार — 72, दिल्ली — 40, गोवा —5, गुजरात—24, हरियाणा — 10, हिमाचल प्रदेश — 5, कर्नाटक — 70, केरल— 425, मध्य प्रदेश—25, महाराष्ट्र—90, उड़ीसा—60, पंजाब—62, राजस्थान— 25, तमिलनाडु— 200, त्रिपुरा—30, उत्तर प्रदेश—16, प. बंगाल—1150, सीटू केंद्र—40, (कुल—2500)

इसके बाद नृसिंह चक्रवर्ती ने संविधान में प्रस्तावित संशोधन प्रस्तुत किया (जिसे हम अलग छाप रहे हैं)

डाक खर्च, मुद्रण कागज आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण सीटू का मासिक मुखपत्र वर्किंग क्लास व सीटू मजदूर की दरें 1 रु से 2 रु प्रति किए जाने और वार्षिक चंदा 20 रु किये जाने के लिए नृसिंह चक्रवर्ती ने जो प्रस्ताव रखा, उसे, चर्चा के बाद, बैठक ने स्वीकार किया.

इसके बाद का. बी टी आर ने छठे सम्मेलन में चर्चा के मुद्दों के बारे में, जिसे राज्य कमेटियों की रिपोर्ट तथा महा-सचिव की रिपोर्ट में शामिल करना चाहिए, व्याख्या करते हुए बेरोजगारी, ट्रेड यूनियन आंदोलन में कामगार महिलाओं व अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर खास तौर से बल दिया. उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमारे काम के प्रश्नों पर विचार को सम्मेलन का एक पुरा सत्र दिया जाना चाहिए. इसलिए, यह जरूरी है कि हर राज्य इकाई अपने प्रतिनिधिमंडल में कामगार महिलाओं को बड़ी संख्या में भेजे. उन्होंने राज्य कमेटियों को पूरी तैयारी के साथ और लिखित भाषण लेकर सम्मेलन में उपस्थित होने का आह्वान किया.

बी टी आर ने सुझाव दिया कि सम्मेलन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रस्ताव कमेटी इसी बैठक में गठित कर ली जाय ताकि वह समय रहते अपनी बैठकें कर सके और सारे प्रस्ताव तैयार कर सके. इसी के मुताबिक प्रस्ताव कमेटी का गठन किया गया जिसमें एन प्रसाद राव, एम. के. पंधे, नृसिंह चक्रवर्ती, विमल रणदिवे. ए. के. पद्मनाबन, अजेय राउत, एस. सूर्यनारायण राव, बीरेन राय, एम. एम. लॉरेंस तथा पी. के. गांगुली (संयोजक) शामिल हैं. बैठक ने यह भी निर्णय लिया कि इस समिति की बैठक जल्द से जल्द दिल्ली में बुलाई जाय और सम्मेलन के लिए सारे प्रस्तावों का मसौदा तैयार करली जाय.

बैठक ने यह फैसला लिया कि सम्मेलन के लिए अपने रिपोर्ट तैयार करते समय राज्य कमेटियां निम्नलिखित मुद्दों को शामिल करते हुए अपने रिपोर्ट केंद्र को भेजें.

1. कानपुर सम्मेलन के फैसले, जिसमें सीटू के कर्तव्य के बारे में निर्देश था, को किस तरह हमारे ट्रेड यूनियन कैडरों तक पहुंचाया गया ?
2. ट्रेड यूनियनों को जन तांत्रिक ढंग से चलाए जाने तथा नीति-निर्धारण के फैसलों में आम मजदूरों की सक्रीय

तथा उत्साहपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

3. हरिजन तथा अल्पसंख्यक समुदाय को ट्रेड यूनियनों में खींचने के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए हैं ?

4. शांति के लिए अभियान किस प्रकार चलाया गया और उसका प्रभाव.

5. फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ अभियान किस तरह चलाया गया

6. निम्नलिखितों के संदर्भ में क्या कदम उठाए गए (a) बेरोजगारों के साथ एकजुटता (b) किसानों व खेत मजदूरों के साथ एकजुटता खासकर पुलिसी हमला के संदर्भ में (c) अन्य ट्रेड यूनियन आंदोलनों के साथ एकजुटता (d) असंगठित मजदूरों को संगठित करने (e) कामगार महिलाओं को संगठित करने तथा ट्रेड यूनियनों के पदों में उन्हें शामिल करने

7. ट्रेड यूनियन एकता

(अ) राष्ट्रीय अभियान समिति के कामकाज.

(ब) संयुक्त आंदोलनों की एक समीक्षा.

8. राज्यों में सीटू की स्वतंत्र गतिविधियां/संघर्षों की समीक्षा.

बैठक ने, समाजवादी देशों के कई ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों को तथा डब्लू एफ टी यू के प्रतिनिधियों को सम्मेलन में आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया है. 24 से 28 फरवरी तक मास्को में होने जा रही ए यू सी सी टी यू की कांग्रेस के लिए सीटू महासचिव समर मुखर्जी को भेजने की सीटू सचिवमण्डल के फैसले के बारे में तथा 22 से 25 अप्रैल तक बर्लिन में एक डी जी बी (जर्मन जनवादी गणराज्य) कांग्रेस में सीटू को आमंत्रित किए जाने के बारे में बताया. बैठक ने एफ डी जी बी कांग्रेस में मो. अमीन को भेजने का फैसला लिया है.

विमल रणदिवे ने कामगार महिलाओं को ट्रेड यूनियन आंदोलन की मुख्यधारा में शामिल किए जाने की बात उठाई और हिन्दी भाषी क्षेत्र में महिलाओं का संघर्ष तेजी से विकसित करने पर बल दिया. इस सिलसिले में उन्होंने वयेस आफ दि वर्किंग विमैन का हिन्दी संस्करण निकाले जाने की जरूरत पर ध्यान खींचा. का. मनोरंजन राय ने दार्जीलिंग के मजदूरों द्वारा पृथकतावादी जी एन एफ एल आंदोलन के खिलाफ चलाए जा रहे बहादुराना संघर्ष का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि संघर्षरत मजदूरों की सहायता कोष के लिए विभिन्न राज्यों से तथा अखिल भारतीय फेडरेशनों से अबतक कुल 41,666/- रु. प्राप्त हुआ है.

बैठक ने कई प्रस्ताव पारित किए जिसमें फूटपरस्त ताकतों के हमले, सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की हड़ताल, औद्योगिक विवाद तथा ट्रेड यूनियन कानूनों में संशोधन, कोयला खदानों में दुर्घटनाएं, जूट उद्योग, बिहार अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रस्ताव मुख्य है. बी टी आर ने प. बंगाल व केरल में आगामी चुनावों पर प्रस्ताव रखा.

अन्त में, बी टी आर ने अपने समापन भाषण में छठे सीटू सम्मेलन को शानदार रूप से सफल बनाने के लिए सम्पूर्ण सांगठनिक शक्ति के साथ लग पड़ने के लिए राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान किया. मजदूर वर्ग के संघर्ष को वर्ग संघर्ष के बिन्दु तक ले जाने के लिए ट्रेड यूनियन एकता कायम करने, देश की एकता व अखण्डता की रक्षा करने तथा साम्राज्यवादी युद्ध की मुहिम व नाभिकीय विनाश के खतरे के खिलाफ विश्व शांति कायम करने एवं समाजवादी उपलब्धियों को सुरक्षित रखने की सीटू द्वारा चलाई जा रही संघर्ष के इतिहास में इस छठे सम्मेलन को एक महत्वपूर्ण घटना बनाने के लिए बी टी आर ने सम्पूर्ण बुलंदी के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया.

फार्म IV

1. प्रकाशन का स्थान	6, तालकटोरा रोड नई दिल्ली-110001
2. प्रकाशन की अवधि	मासिक
3. मुद्रक का नाम	एम.के. पंधे
क्या भारतीय नागरिक है?	हां
पता	6, तालकटोरा रोड नई दिल्ली-110001
4. प्रकाशक का नाम	एम.के. पंधे
क्या भारतीय नागरिक हैं ?	हां
5. सम्पादक का नाम	एम.के. पंधे
क्या भारतीय नागरिक हैं ?	हां 6, तालकटोरा रोड नई दिल्ली-110001
6. उन लोगों के नाम जो पत्र के स्वामी और हिस्सेदार हैं अथवा सम्पूर्ण पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार हैं.	सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स

मैं, एम.के. पंधे एतद द्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के आधार पर सही है.

हस्ताक्षरित
एम.के. पंधे
प्रकाशक

दिनांक : 28 फरवरी, 1987

सीटू वर्किंग कमेटी द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव

नाभिकीय परीक्षणों पर

कलकत्ता में, 6 व 7 फरवरी 1987 को सम्पन्न सीटू कार्य कारिणी की यह बैठक विश्व जनमत की उपेक्षा कर नाभिकीय परीक्षण चलाने के लिए अमरीकी प्रशासन की तीव्र भर्त्सना करती है. इससे ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया कि अब सोवियत संघ को मजबूरन नाभिकीय परीक्षणों पर डेढ़ साल पुरानी एकतरफा रोक हटानी पड़ेगी. अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा परीक्षण चलाते रहना सोवियत संघ के खिलाफ उसके युद्ध की घिनौना साजिशों को और इस तरह हथियारों की होड़ तेज करने तथा दुनिया को नाभिकीय विनाश के कगार पर ढकेलने के मंसूबों को ही बेनकाब करता है. यह बैठक, रिक्यावि‍क वर्ता के विफल होने के लिए अमरीका को ही जिम्मेदार ठहराती है जिसने अन्तरिक्ष युद्ध के कार्यक्रम को वापस न लेने पर अड़े रहे. यह बैठक अमरीकी सरकार से मांग करती है कि वह बातचीत के लिए तैयार हो ताकि हथियारों में कटौती पर समझौता हो सके तथा नाभिकीय खतरे से मुक्त 21वीं सदी की ओर बढ़ा जा सके.

बैठक उन यूनियनों को बधाई देती है जो सीटू सचिवमण्डल के फैसले के मुताबिक राष्ट्रपति रीगन के नाम तार भेजकर अपना विरोध जताया है तथा नाभिकीय परीक्षणों को बंद करने की मांग की है. यह बैठक अपने राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वह शांति के लिए संघर्ष को लगातार कार्यक्रमों के जरिए तेज करें. इस सवाल पर ट्रेड यूनियनों तथा अन्य विभिन्न संगठनों के बीच बढ़ते एकता की रूझान का, जिससे देश में शांति आंदोलन के लिए उभर रही व्यापक मंच को एक नई दिशा मिलेगी, यह बैठक स्वागत करती है.

फूटपरस्त ताकतों पर

कलकत्ता में 6 व 7 फरवरी 1987 तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक देश में फूटपरस्त तकतों की बढ़ती गतिविधियों पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है. पंजाब में, समझौते को लागू न करने के कारण खालिस्तानी पृथकतावादियों को बल मिला है और ये ताकतें एक बार फिर धर्म को राजनीति से जोड़कर बरनाला सरकार पर फिर से हमला बोल दिया है. प. बंगाल में जी एन एल एफ की हिंसक और विघटनकारी गतिविधियां बे-रोक-टोक जारी है. उत्तरी पूर्व क्षेत्र में, मिजोरम समझौते के बाद, उग्रवादी तत्वों ने, खासकर त्रिपुरा में टी एन वी ने, अपने हरकतों को तेज कर दिया है. देश के दूसरे भागों में भी, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने गणतंत्र दिवस समारोहों का बहिष्कार करने का आह्वान के जरिये सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जिससे हिंदू सांप्रदायिकता भड़काने वालों को भी हरकत में आने का मौका मिला भाषायी उन्मादना जैसा तमिलनाडु और गोआ में देखा गया, भी एक गंभीर चिंता का विषय है.

इस भयानक स्थिति में, जो देश की एकता व अखण्डता को ही खतरे में डालती है, सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि केन्द्र तथा राज्यों की कांग्रेस (आइ) सरकारें इन अलगाववादी तथा फूटपरस्त ताकतों के पीछे उन साम्राज्यवादी एजेंसियों की साजिशों को देख पाने में असमर्थ है जो देश को टुकड़े-टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं.

साम्राजियों के मददप्राप्त इन फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ जनता को लामबंद करने के बजाय कांग्रेस (आइ) सरकार, अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए, इन्हीं ताकतों को खुश करने और उससे समझौता करने की अपनी रवैये को जारी रखा है.

साम्राज्यवादी साजिशों को शिकस्त देने और देश की एकता व अखण्डता की रक्षा में उनके बहादुराना संघर्ष के लिए यह बैठक, अपने राज्य कमेटियों तथा सीटू यूनियनों को, खासकर पंजाब, असम, त्रिपुरा तथा प. बंगाल और विशेष तौर पर दार्जीलिंग जिला एवं जलपाइगुड़ी समतल भूमि के मजदूरों जो अधिकतर नेपाली हैं, को बधाई देती है. इस सवाल पर संघर्ष को तेज करने के लिए बैठक, ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति का आह्वान करती है.

सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की हड़ताल पर

कलकत्ता में 6 व 7 फरवरी 1987 को सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक 21 जनवरी की शानदार हड़ताल के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का गर्मजोशी से अभिनन्दन करती है. इस हड़ताल के प्रति शानदार एकजुटता कार्रवाई के प्रदर्शन के लिए बैठक निजी क्षेत्र के एवं अन्य तमाम तबके के मजदूर कर्मचारियों का भी अभिनंदन करती है. कई स्थानों में निजी क्षेत्र के मजदूर भी हड़ताल में शामिल हुए जहां बंद का रूप लिया.

केन्द्र सरकार की प्रतिगामी आर्थिक नीति, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करने की उसकी मुहिम तथा बहुराष्ट्रीय निगमों व देशी इजारेदारों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संरक्षित दायरे में घुसपैठ की इजाजत देने की सरकार की नीतियों में ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा हस्तक्षेप करने की दिशा में यह हड़ताल की कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम है. सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करते हुए कर्मचारियों ने देश की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता की हिफाजत तथा विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबावों से इसे मुक्त करने की अपनी दृढ़ निश्चय का ही इजहार किया (शेष पृष्ठ 18 पर)

बिहार एन. जी. ओ नेताओं की गिरफ्तारी की सीटू द्वारा भर्त्सना

सीटू महासचिव समर मुखर्जी ने 18 फरवरी को निम्नलिखत बयान जारी किया है :

राज्य के हड़ताली कर्मचारियों को, जो चौथे वेतन आयोग के बाद समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे है, को डराने धमकाने के उद्देश्य से 15 एन जी ओ नेताओं को गिरफ्तार करने की बिहार सरकार की कार्रवाई की सीटू तीव्र निंदा करती है. इस बात को देखते हुए कि प्रायः सभी राज्यों में, जहां इस मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी संघर्ष में गए, वहां के राज्य सरकारों ने समझौता कर लिया, बिहार सरकार की यह कार्रवाई बहुत ही भर्त्सना योग्य है और खासकर इस वजह से भी कि इससे पहले कई मौकों पर हड़ताल वापस लेने के पहले दिए गए आश्वासनों तक को लागू नहीं किया गया.

बाम पार्टियों द्वारा 21 फरवरी को बिहारबन्द के लिए दिए गए आह्वान का सीटू सम्पूर्ण समर्थन करती है और बिहार के मजदूरवर्ग का आह्वान करती है कि वह सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के प्रति सम्पूर्ण समर्थन का इजहार करने के लिए एक दिन की एकजुटता हड़ताल में शानदार ढंग से शिरकत करें.

[20 फरवरी को समझौता हो जाने के कारण हड़ताल वापस ले लिया गया. गिरफ्तार नेताओं को भी रिहा कर दिया गया है.]

सीटू वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव
बिहार राज्य सरकारी कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

कलकत्ता में 6 व 7 फरवरी 1987 तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक, बिहार के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों तथा शिक्षकों को, उनकी 15 सूत्री मांगपत्र, जिसमें केन्द्र सरकारी कर्मचारियों जैसा वेतन में समानता की मांग शामिल है, के समर्थन में 20 जनवरी से शानदार ढंग से चलाई जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बधाई देती है. यह बैठक, नगरपालिका कर्मचारियों को भी बधाई देती है जो 20 जनवरी से हड़ताल पर हैं.

यह बैठक बिहार सरकार की तीव्र भर्त्सना करती है जिसने सी आर पी तैनात कर तथा सेना को तैयार रखकर मजदूर कर्मचारियों पर व्यापकरूप से दमनात्मक कार्रवाइयां चला रखा है. सरकार, 20 हजार कर्मचारियों को हिरासत में ले चुकि है तथा एसमा, एन एस ए एवं सम्बिधान की धारा 311 के तहत और भी दमनात्मक कदम उठाने की धमकी दी है.

यह बैठक राज्य सरकार से मांग करती है कि वह तमाम दमनात्मक कार्रवाइयां वापस लें तथा मजदूर कर्मचारियों की जायज मांगों को स्वीकार कर स्थिति को सामान्य बनायें.

संविधान में संशोधन

कलकत्ता में, 6 व 7 फरवरी 1987 को हुई सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक ने मई 18 से 22, 1987, तक बम्बई में होने जा रही सीटू सम्मेलन में सीटू संविधान में निम्नलिखित संशोधन पेश करने का फैसला लिया है.

धारा-5, उपधारा (ii)

शब्द "द्विवार्षिक" के स्थान पर "त्रिवार्षिक" जोड़ा जाय.

धारा-6, उपधारा (i)

प्रथम पंक्ति में शब्द "दो" के स्थान पर "तीन"

धारा-15

1. उपधारा (c): वर्तमान उपधारा (c) के बदले में निम्नलिखित उपधारा (c) जोड़ा जाय, "कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिए जनरल काउंसिल या/और राज्य कमेटियों द्वारा निर्धारित अन्य ऐसे सभी रकम"

2. उपधारा (d) के बदले में निम्न उपधारा (d) "ऊपर के (a), (b) तथा (c) में देय तीनों रकम सम्बद्धता शुल्क का ही अभिन्न हिस्सा है"

कृपया इन संशोधनों पर विचार विमर्श करें और आपके प्रतिनिधिमण्डल को स्थिति से अवगत कराएं.

समर मुखर्जी
महासचिव

सीटू मजदूर व वर्किंग क्लास के ग्राहकों के प्रति

साथियों,

पिछले कुछ अर्से से सीटू मजदूर तथा वर्किंग क्लास पत्रिका घाटे में चल रही है. हम इस घाटे को, कुछ विज्ञापनों के माध्यम से कम करने का प्रयास करते रहे है. पर पिछले वर्ष (1986) से स्थिति और भी खराब होती चली गई.

1 जनवरी 1987 से डाक दरों में बढ़ोत्तरी से एक प्रति पर 10 पैसे डाक खर्च बढ़ गया है. इसलिए, सीटू कार्यकारिणी को मजबूरन इन दोनों पत्रिकाओं की कीमतें बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा. अब हर प्रति की कीमत 2 रु. होगी. ग्राहकों के लिए वार्षिक दर 20 रु. किया गया है.

नयी दरें, 6.2.87 से लागू होगी. हमें आशा है कि आप हमारी मजबूरी को समझकर अपना सहयोग हमेशा की तरह बनाए रखेंगे.

नृसिंह चक्रवर्ती
सचिव

द्वारा बुलाई गई बैठक में मजदूरों तथा मालिकान के प्रतिनिधियों के बीच काफी गरमा-गरम बहस हुई, मजदूरों के प्रतिनिधियों में से सीटू के पी के गांगुली तथा एटक के टी एन सिद्धांत मुख्य बक्ता थे, मालिकान की तरफ से इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के महासचिव तथा साउथ इंडिया शुगर मिल एसोसिएन के सचिव बोले. उन्होंने कोई भी मांग मानने से इनकार कर दिया.

17 फरवरी को समन्वय समिति की फिर बैठक हुई, जिसमें संयुक्त कन्वेंशनें आयोजित करने और हर चीनी उत्पादक राज्य में गेट मीटिंगों का आयोजन कर आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

उधर, वेजबोर्ड ने 18-19 फरवरी को अपनी अलग से मीटिंग आयोजित की. समझा जाता है कि इस मीटिंग में दोनों मुद्दों पर सदस्यों में तीव्र मतभेद रहे और कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका. अब 8 मार्च को कोल्हापुर में वेज बोर्ड की अगली बैठक होनेवाली है. अब इस बैठक में अगर कोई आम राय नही बनी, तो हर सदस्य अपनी व्यक्तिगत राय सरकार को देगा.

यह तय है कि जब तक एक संयुक्त आंदोलन नहीं खड़ा किया जायेगा, ये दोनों मांगें पूरी होनेवाली नहीं हैं, पूरे मांग-पत्र पर सुनवाई 2-3 महीने बाद होने वाली है, इससे पहले वेज बोर्ड विभिन्न राज्यों के अपने दोरे पूरे कर लेगा, इसलिए, सीटू की तमाम चीनी मिल मजदूर यूनियनों और राज्य कमेटियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द अपनी स्थिति मजबूत करें और कन्वेंशनों तथा गेट मीटिंगों का आयोजन कर तथा पर्चे बांटकर संयुक्त आंदोलन शुरू करें.

(पृष्ठ 8 का शेष)

है. इस कार्रवाई के जरिये कर्मचारियों ने सरकार से ऐसी तकनीकी आयात को रोकने, जो घरेलू विकास के लिए हानिकारक है तथा ट्रेड यूनियनों की पूर्वानुमति के बिना आधुनिकीकरण व कम्प्यूटीकरण लागू न करने का आग्रह किया है.

सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की यह विशाल हड़ताल, सांप्रदायिक व फूटपरस्त ताकतों की बाधाओं को तोड़ते हुए लाखों मजदूरों को लामबंद करने की ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्षमता को ही उजागर करता है.

यह बैठक, सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधकों को चेतावनी देती है कि वे मजदूरों पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न चलाएं और वेतन में कटौती सहित अन्य तमाम दंडात्मक कदम वापस लेने की मांग करती है.

इस विरोध कार्रवाई के प्रति जबर्दस्त समर्थन मजदूर बर्ग के उस बढ़ते इरादों को ही दिखाता है कि देश एवं तमाम जनता के हित में एक वैकल्पिक आर्थिक नीति पेश करने के लिए मजदूर वर्ग अब तैयार हैं.

हड़ताल की सफलता के लिए यह बैठक, सार्वजनिक क्षेत्र यूनियनों की स्टियरिंग कमेटी को बधाई देती है और उससे आग्रह करती है कि हड़ताल के माध्यम हासिल एकता को और भी मजबूत बनाने के लिए कारगर कदम उठाएं. यह बैठक हड़ताल में शिरकत न करने वाले यूनियनों से अपील करती हैं कि राष्ट्र के हित में वह आंदोलन की मुख्यधारा में शामिल हो.

पं. बंगाल व केरल के चुनावों पर

कलकत्ता में 6 व 7 फरवरी 1987 को आयोजित सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक प. बंगाल एवं केरल की जनता व मजदूर वर्ग से अपील करती है कि मार्च 1987 में होने जा रही विधान सभा चुनावों में बाम मोर्चा के उम्मीदवारों को वोट दें और उनकी जीत सुनिश्चित करें. वे इस तथ्य पर जरूर गौर किए होंगे कि प. बंगाल में सी पी आई (एम) की नेतृत्ववाली वाम मोर्चा सरकार तथा कांग्रेस (आई) की नेतृत्व वाली केरल की यू डी एफ सरकार दो भिन्न नीतियों पर चल रही है. जब कि प. बंगाल में सरकार, केन्द्र की कांग्रेस (आई) सरकार की नितियों के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व आर्थिक कठिनाइयों से पीस रही जनता को राहत दिलाने की हर संभव प्रयत्न करती रही है, कांग्रेस (आई) की नेतृत्व वाली केरल की यू डी एफ सरकार लोगों को मिल रही राहत जैसा बेरोजगारी राहत, भी वापस लेती रही है. केरल के लोगों का खुद अपना यह अनुभव रहा है कि जब कभी भी उन्होंने किसी चीज के विरोध में आवाज उठाया, उन पर बर्बर दमन चलाया गया जबकि प. बंगाल की जनता को जनवादी आंदोलन चलाने की पूरी आजादी है. प. बंगाल की सरकार, देश की अखंडता की रक्षा के लिए तथा फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ लड़ती रही है जबकि केरल की कांग्रेस (आई) सरकार अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए सांप्रदायिक एवं जातियतावादी ताकतों से समझौता करती रही है.

सीटू का यह दृढ़ विश्वास है कि प. बंगाल तथा केरल की जनता एवं मजदूरवर्ग वोट देते समय इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि केंद्र की कांग्रेस (आई) सरकार ट्रेड यूनियन एवं हड़ताल सहित तमाम जुझारू कार्रवाइयों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में संशोधन लाने की साजिश कर रही है और वाम मोर्चे की उम्मीदवारों को विजयी बनायेंगे ताकि इन दो राज्यों की सरकारें, महंगाई के खिलाफ वेतन में आई गिरावट के खिलाफ तथा अपने रोजगार और जीवन स्तर को सुरक्षित रखने एवं देश की एकता व अखंडता की रक्षा के लिए, इस देश की जनता द्वारा चलाई जा रहा संघर्ष में उन्हें मदद दे सकें.

इन्डोनेशिया के मजदूरवर्ग नेताओं को सजाए मौत

कलकता में, 6 व 7 फरवरी 1987 तक सम्पन्न कार्यकारिणी की यह बैठक इडोनेशियाई अधिकारियों की तीव्र भर्त्सना करती है जो एस ओ बी एस आई के भूतपूर्व उपाध्यक्ष का. रूसलन बिजयाशास्त्र एवं इन्डोनेशिया के अन्य मजदूर नेताओं को सजाए मौत का दण्ड देने की साजिश में जुटे हुए हैं.

इन नेताओं को पिछले बीस सालों से, बिना बिचार के तथा बचाव का मौका दिए बिना, जेलों में रखा गया है. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर जनरल के हस्तक्षेप के बावजूद तथा बिश्व मजदूरवर्ग आंदोलन के विरोध के बावजूद इण्डोनेशियाई अधिकारी इस मामले में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं. यह बैठक इस दण्ड को रद्द करने तथा राजनीतिक बन्दियों को तत्काल रिहा करने की मांग करती है.

ट्रेड यूनियन तथा औद्योगिक विवाद कानून में संशोधन पर

कलकत्ता में 6 व 7 फरवरी 1987 तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक भारत साकार की निंदा करती है जो केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के एकजुट विरोध के बावजूद भी ट्रेड यूनियन कानून तथा औद्योगिक विवाद कानूनों में प्रतिगामी संशोधन लाने पर उतारू है. इन प्रतिगामी संशोधनों को नामंजूर करने की अपनी पूर्व सिद्धांत को दोहराते हुए यह बैठक सरकार को चेतावनी देती है कि मजदूरवर्ग कभी भी सामूहिक सौदेबाजी की अपनी कीमती हथियार अर्थात हड़ताल करने की अधिकार तथा ट्रेड यूनियन गतिविधियों की स्वतन्त्रता—जिसे वर्षों की संघर्ष से उसने हासिल किया है, को उससे छीनने का अधिकार नहीं देगी.

प्रस्तावित इन प्रतिगामी संशोधनों के खिलाफ एकजुट आंदोलन के निर्माण के लिए पहलकदमी के लिए यह बैठक राष्ट्रीय अभियान समिति का अभिनन्दन करती है और सभी ट्रेड यूनियन केन्द्रों तथा राष्ट्रीय फेडरेशनों से इस साजिश को नाकाम करने की अपील करती है. यह बैठक अपने राज्य कमेटियों को निर्देश देती है कि वह एक लम्बी संघर्ष के लिए मजदूरवर्ग को तैयार करें ताकि सरकार को अपनी कदम वापस खींचने के लिए मजबूर किया जा सके.

कोयला खदानों में दुर्घटनाओं पर

कलकत्ता में 6 व 7 फरवरी 1987 तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक कोयला खदानों में घातक और गम्भीर दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता प्रकट करती है. सी ई एल के राजरप्पा कोयला खदान में हाल की भयंकर दुर्घटना, ई सी एल कोलियरी में पानी का भर जाने से एक मजदूर की मौत तथा कालिपाहाड़ी कोयला खदान में जहां चार महिला मजदूरिने जिंदा दबकर मर गई, इस बात की ओर संकेत करता है कि कोल इण्डिया के अधिकारीगण खदानों में सुरक्षा और आस-पास के क्षेत्रों में जान-माल की सुरक्षा के सवाल पर अपराधीपूर्ण लापरवाही बरत रहे हैं जिसके लिए वे भर्त्सनायोग्य पात्र है.

यह बैठक दुर्घटना में मारे गए उन मजदूरों के लिए शोक का इजहार करती है और उनके शोक संतप्त परिवारजनो को सम्पूर्ण मुआबजा देने, दुर्घटनाओं की जांच करने और दोषी व्यक्तियों को सजा देने की मांग करती है. यह बैठक खदान मजदूरों के ट्रेड यूनियनों का आह्वान करती है कि वे खदानों में सुरक्षा प्रावधानों को पूरी तरह लागू करवाने के लिए एकजुट आंदोलन का निर्माण करें.

जूट उद्योग पर

कलकत्ता में 6 व 7 फरवरी 1987 तक सम्पन्न सीटू की कार्यकारिणी की यह बैठक एक लाख टन कृत्रिम रेशों से बनी बैग, जो कि पांच लाख टन जूट बैगों के समान है, के उत्पादन से जूट उद्योग के सामने उत्पन्न संकट पर गहरी चिंता प्रकट करती है कृत्तिम रेशों से बनी बैग के उत्पादन से जूट बैगों के 50 फीसद घरेलू बाजार खत्म हो जायगा. पिछले कई सालों से प्रतिवर्ष 85 करोड़ रु. की कीमती विदेशी मुद्रा खर्चकर ओपन जनरल लाइसेंस के तहत पी वी सी ग्रैन्यूलस आयात किए जाने की खतरनाक परिणामों के बारे में सीटू चेतावनी देती चली आ रही है.

इसके अलावा, जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए 250 करोड़ रु. दिए जाने की केन्द्र सरकार की घोषणा भी एक धोखाधड़ी है क्योंकि यह पैसा आधुनिकीकरण के चलते जूट मिलों का स्थायी रूप से बन्द हो जाने के फलस्वरूप बेरोजगार होनेवाले मजदूरों को "स्वर्णिम बिदाई" की योजना के तहत दिए जानेवाले मुआवजे के रूप में ही इस्तेमाल किया जायगा. अनुमान है कि आधुनिकीकरण के चलते करीब 20 मिलें बन्द हो जायेगी तथा 75 हजार मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे और बाकी बचे मजदूरों पर बढ़े हुए काम का बोझ थोप दिया जायगा.

यह बैठक, जूट मजदूरों का अभिनन्दन करती है जिन्होंने अतीत में इस तरह के संकटपूर्ण स्थिति को एकजुट होकर झेला है, और ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि हासिल इस एकता की वे रक्षा करें तथा उसे और मजबूत बनाएं ताकि इस अभूतपूर्व हमले का मुकाबला किया जा सके और एक लम्बे संघर्ष के लिए भी तैयार हो जिससे कि जूट उद्योग को बर्बाद करने की नीति को सरकार को बदलने के लिए तथा राष्ट्रीयकरण की मांग को स्वीकार करने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सके.